मोती उत्पादन को करें प्रोत्साहित

मछुआ कल्याण व मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 22 जून. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एकीकृत मत्स्योघोग नीति: 2026 के कारण प्रदेश में मछली पालन सेक्टर में 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ रहा है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नदियों के पुनर्जीवन, जलीय जीवों के संरक्षण के लिए सभी संबंधित विभाग परस्पर समन्वय से कार्य करें. जलीय ईको सिस्टम को विकसित करने और जल सम्पदा पर आधारित पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाये. मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अन्तर्देशीय जल क्षेत्र में मप्र देश में दूसरे स्थान पर है.

प्रदेश में मोती उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाये, इसके लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर उनका क्रियान्वयन प्रदेश में सुनिश्चित किया जायें. प्रदेश को मछली उत्पादन में आत्म निर्भर बनाना जरूरी है. अगले ढाई साल में हमें मछली बीज अन्य स्थानों से नहीं खरीदना पड़े, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर विभाग कार्य करे. हर जिले में एक हेचरी आवश्यक रूप से विकसित की जाये. जिलों में मछली बीज आसानी से मिलने से प्रदेश में मछली उत्पादन में और बढ़ोत्तरी होगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मंत्रालय में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे मछली उत्पादन को देखते हुए कोल्ड चेन तथा अन्य आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाये. ब्रांडिंग और निर्यात के लिए आवश्यक नेटवर्किंग को भी प्रोत्साहित किया जाये.

'गोल्डन ऑवर हीरो' अभियान से सड़क हादसों में 33% कमी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जून. नरसिंहपुर पुलिस द्वारा शुरू की गई अभिनव सड़क सुरक्षा पहल 'गोल्डन ऑवर हीरो' ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और गंभीर रूप से घायल होने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज कराई है.

वर्ष 2026 के जनवरी से मई के बीच इस अभियान के प्रभाव से सड़क दुर्घटनाओं में 33 प्रतिशत, मृत्यु दर में 23 प्रतिशत तथा गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों की संख्या में 52 प्रतिशत की कमी आई है. सड़क दुर्घटना के बाद का पहला घंटा, जिसे 'गोल्डन ऑवर' कहा जाता है, पीड़ित के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए नरसिंहपुर पुलिस ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित ढाबा संचालकों, पेट्रोल पंप कर्मचारियों तथा स्थानीय ग्रामीणों को चिन्हित कर उन्हें सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया. आपातकालीन सहायता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष व्हाट्सएप समूह बनाए गए, सरकारी राहत योजनाओं की जानकारी दी गई तथा फर्स्ट एड बॉक्स वितरित किए गए. इन प्रयासों से दुर्घटना पीड़ितों तक त्वरित सहायता पहुंचाने में सफलता मिली.

प्री-मानसून में झमाझम बारिश होने से ठंडक

धार, उज्जैन, भोपाल सहित कई जिलों में हुई बरसात

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 22 जून. मप्र में प्री-मानसून के दौरान झमाझम बारिश की शूरूआत हो गई है. सोमवार को प्रदेश के धार, उज्जैन, बड़वानी, रायसेन, भोपाल सहित कई जिलों में बारिश होने से ठंडक बनी रही.

इन जिलों में करीब आधे घंटे तक बारिश होती रही. देर शाम तक रिमझिम बारिश का दौर भी इस बीच जारी रहा है. मौसम विभाग ने प्रदेश में 25 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई है. मानसून के आने से पहले ही प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी हो चुका है. मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों में भी जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. राजगढ़, शाजापुर, आगर, दमोह, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनुपपुर, जबलपुर सहित जिलों में बारिश की संभावना जताई है. जिलों में बिजली के साथ मध्यम गरज (हवा की गति 60 किमी प्रति घंटे) के साथ-साथ रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी में बिजली (40 किमी प्रति घंटे तक की हवा) के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना है. इंदौर, देवास, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, चित्रकूट, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली सहित जिलों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है.

इंदौर में हल्की बारिश

सोमवार को शहर में हल्की बारिश हुई. इससे गर्मी और उमस से आमजन को राहत मिली है. आज दिन का तापमान सामान्य ही रहा, लेकिन रात का तापमान 2 डिग्री ज्यादा 25.6 डिग्री दर्ज हुआ. शहर में अभी तक 55.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है. आज दिन में मात्र 3 मिली मीटर वर्षा हुई. इस बार बारिश के हिसाब से जून महीना सुखा रहने की संभावना बढ़ गई है. अरब सागर में दक्षिण पश्चिम मानसून आज बढ़ा है और मध्य प्रदेश पहुंचने में एक हफ्ते का समय लेगा. मानसून इससे ज्यादा भी समय ले सकता है, या आगे बढ़ने की गति पर निर्भर करता है.

नैवेद्य लोक की दुकानों के लिए उमड़ा उत्साह

- 34 दुकानों पर आए 82 आवेदन
- इंदौर की 56 दुकान की तर्ज पर विकसित फूड जोन
- कारोबारियों में जबरदस्त रुचि

नवभारत न्यूज

उज्जैन. शहर में विकसित किए जा रहे नए व्यावसायिक और पर्यटन केंद्र नेवध लोक को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है. नानाखेड़ा बस स्टैंड के समीप उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित नैवेध लोक की 34 दुकानों के आवंटन के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में 82 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

सोमवार को टेंडर खुलने के बाद अब सभी आवेदनों की तकनीकी और दस्तावेजी जांच की जा रही है. अंतिम निर्णय अगले दो से तीन दिनों में लिया जा सकता है.

सीएम की परिकल्पना -नेवध लोक का निर्माण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर किया गया है. इसका भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने किया था. महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को आधुनिक फूड स्ट्रीट का अनुभव देने के उद्देश्य से इस परियोजना को विकसित किया गया है. यह परिसर इंदौर की प्रसिद्ध 56 दुकान की तर्ज पर तैयार किया गया है, जहां विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रतिष्ठान और खानपान से जुड़े व्यवसाय संचालित होंगे.

1 दुकान में 14 फार्म -टेंडर प्रक्रिया में प्राप्त आवेदनों से स्पष्ट है कि कारोबारियों को इस परियोजना की व्यावसायिक संभावनाओं पर पूरा भरोसा है. कई दुकानों के लिए 10 से 14 तक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि अधिकांश दुकानों के लिए एक से अधिक दावेदार सामने आए हैं. अब विकास प्राधिकरण सभी आवेदनों की तकनीकी पात्रता, दस्तावेजों और अन्य आवश्यक शर्तों की जांच कर रहा है. किसी आवेदन में तकनीकी त्रुटि या दस्तावेजी कमी पाए जाने पर उसे नियमानुसार परखा जाएगा.

रोजगार का सृजन

नैवेध लोक शुरू होने के बाद न केवल स्थानीय व्यापार को नई गति मिलेगी, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. महाकाल मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहां रुककर खानपान का आनंद ले सकेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. टेंडर प्रक्रिया में अपेक्षा से अधिक आवेदन प्राप्त होना इस बात का संकेत है कि उज्जैन में विकसित हो रहे नए व्यापारिक केंद्रों पर निवेशकों और कारोबारियों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है.

30 से 90 लाख की दुकान

नवभारत से चर्चा मे विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नैवेध लोक की दुकानों की कीमत लगभग 30 लाख रुपये से लेकर 90 लाख रुपये तक निर्धारित की गई थी. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन कर यह संकेत दिया है कि उज्जैन का व्यावसायिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है. महाकाल लोक और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच शहर में पर्यटन, व्यापार और निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं. नैवेध लोक का स्थान भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता माना जा रहा है. यह परिसर नानाखेड़ा अंतरराज्यीय बस स्टैंड के ठीक समीप स्थित है. आसपास प्रतिकल्पा जैसे व्यावसायिक एवं आवासीय प्रोजेक्ट विकसित हो चुके हैं, जबकि सी-21 मॉल भी पहले से संचालित है. ऐसे में यह क्षेत्र उज्जैन के नए कमर्शियल हब के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है.

यूसीसी पर भाजपा के महत्वपूर्ण सुझाव

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 22 जून. प्रदेश भाजपा ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की समिति को सौंपे हैं.

पार्टी के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी और एक अन्य पदाधिकारी एस. एस. उप्पल ने सुझाव पत्र सौंपा. पत्र में विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर कड़े कानून बनाने का अनुरोध किया गया है. सुझाव पत्र में विवाह में पूर्ण पारदर्शिता रखने पर विशेष जोर दिया गया है. पार्टी का सुझाव है कि शादी से पहले दोनों पक्षों द्वारा अपनी पहचान, नागरिकता, वैवाहिक स्थिति और पूर्व विवाह या तलाक से जुड़े तथ्यों का प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाए. वहीं जानबूझकर तथ्य छिपाने या गलत जानकारी देकर विवाह करने को दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए.

पार्टी द्वारा सौंपे गए सुझाव: 1. पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम कानूनी आयु का सख्ती से पालन कराना
2. पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति में बेटे और बेटी को समान अधिकार, साथी की मृत्यु के बाद जीवित जीवनसाथी के अधिकार सुरक्षित हों.
सभी नागरिकों को बच्चा गोद लेने का कानूनी अधिकार और उन्हें समान रूप से संपत्ति में अधिकार दिलाना. 3. बच्चों के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में माता और पिता दोनों को समान कानूनी दर्जा दिया जाए. 4. विवाह, तलाक या भरण-पोषण से जुड़े पारिवारिक विवादों का निपटारा अधिकतम 6 महीने के भीतर हो.

मंदिर ट्रस्टों की वित्तीय जांच की मांग

कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जून. मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने देश के प्रमुख मंदिर ट्रस्टों और धार्मिक परियोजनाओं की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए उनकी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.

उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े विभिन्न मंदिर ट्रस्टों ने धर्म, आस्था और सनातन परंपराओं के नाम पर जनता की भावनाओं का राजनीतिक उपयोग किया है, जबकि कई बड़े धार्मिक प्रकल्पों से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का अब तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है. मुकेश नायक ने कहा कि उज्जैन के महाकाल लोक तथा ओरछा में प्रस्तावित श्रीराम महालोक परियोजना समेत कई मंदिर विकास एवं पुनरुद्धार योजनाओं पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि ओरछा परियोजना में 50 रुपये प्रति वर्गफुट कीमत वाली टाइलें कथित रूप से 350 रुपये प्रति वर्गफुट तक की दर पर खरीदी गईं,

बेटमा में किसान का अपहरण, 20 लाख फिरौती मांगी

- पुलिस की हलचल देखकर भागे बदमाश

इंदौर. बेटमा थाना क्षेत्र में एक किसान का अपहरण कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. पुलिस के मौके पर पहुंचने की भनक लगते ही बदमाश किसान को छोड़कर फरार हो गए.

जिले के बेटमा थाना क्षेत्र के पंथ बड़ौदिया गांव में रहने वाले किसान हुकुमसिंह शुक्रवार रात खेत में जाने का कहकर घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे. इसी बीच उनके मोबाइल से ही परिजनों के पास वाट्सऐप कॉल और वाइस मैसेज आने लगे, जिनमें

अपहरणकर्ताओं द्वारा 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई. परिजनों ने जब कॉल कर बात करने की कोशिश की तो सामने से किसान की तस्वीर भेजी गई, जिसमें उसे नीचे दबाकर उसके गले पर चाकू अड़ा हुआ दिखाई दे रहा था. इसके बाद आरोपियों ने एक सुनसान स्थान पर रकम लेकर पहुंचने को कहा.

घटना से घबराए परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ग्रामीणों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंची. वहां हलचल बढ़ती देख अपहरणकर्ता किसान को लेकर भाग निकले, लेकिन कुछ दूरी पर ही उसे छोड़कर फरार हो गए. रातभर परिजन इंतजार करते रहे और सुबह किसान किसी तरह घर पहुंच गया. बताया जा रहा है कि वह नशे की हालत में था, जिसके कारण घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा है. पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. मामले में बेटमा थाना प्रभारी मीना कर्णावत ने बताया कि फरियादी अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, उसके बयान के बाद ही घटना के संबंध में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.

पटवारियों के 411 पद मंजूर

नवभारत न्यूज

सीधी 22 जून. जिले में पटवारियों की कमी के चलते राजस्व कार्य काफी प्रभावित हो रहे हैं. स्थिति यह है कि सीधी जिले में पटवारियों को 411 पद स्वीकृत हैं. इसके विरुद्ध महज 267 पटवारी पदस्थ हैं.

पटवारियों की कमी के चलते एक पटवारी को दो-तीन हल्कों का प्रभार सौंपा गया है. ऐसी स्थिति में प्रभार वाले पटवारी हल्कों का कार्य सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है. पटवारियों की कमी के चलते किसानों के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. समय के साथ सीधी जिले में पटवारी हल्कों की संख्या में बढ़ोत्तरी भी की गई है. जिले में 8 तहसीलें हैं जहां गांवों की संख्या करीब 1072 है. इतने बड़े क्षेत्र के मुकाबले केवल 267 पटवारी ही पदस्थ हैं. जबकि 144 पटवारियों के पद रिक्त पड़े हैं. कुछ पटवारी रिश्वतखोरी के चलते लोकायुक्त के शिकंजे में भी फंस चुके हैं. वहीं कुछ को कार्यालय में अटैच किया गया है. पिछले कई माह से पटवारियों की कमी की समस्या बनी हुई है. विडम्बना यह है कि जिला स्तर से उक्त समस्या की जानकारी राज्य सरकार को भेजी जाती है फिर भी शासन स्तर से पटवारियों की कमी को पूरा करने के लिए वैकेंसी निकालने की जरूरत नहीं समझी जा रही है. शासन द्वारा आवश्यक संख्या में पटवारियों की भर्ती नहीं की जाती.

स्कूल वाहन पलटा, सात बच्चे घायल

छिंदवाड़ा. कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को एक स्कूल वेन अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में सात बच्चे घायल हो गए. हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है. दो बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया. वही पांच बच्चे को निजी अस्पताल ले जाया गया. एक बच्चे को छोड़कर अन्य बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. एक निजी स्कूल के बच्चे छुट्टी होने के बाद स्कूल वाहन से घर लौट रहे थे. इस दौरान वाहन चालक ने कुछ बच्चों को घर छोड़ दिया था. तकरीबन सात बच्चों को लेकर वह घर छोडने जा रहा था. इस दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया और ओवर ब्रिज की बाउंड्री बॉल में जा घुसा.

यूसीसी : असली मुद्दों से ध्यान भटकाया

मूलभूत मुद्दों पर जवाब देने के बजाय सरकार यूसीसी की बहस कर रही

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जून. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने को लेकर चल रही चर्चा भारतीय जनता पार्टी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता का ध्यान प्रदेश के ज्वलंत सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से हटाना है।

एक बयान में पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता इस समय बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और आदिवासी समुदाय के कल्याण से जुड़े गंभीर प्रश्नों का सामना कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मूलभूत मुद्दों पर जवाब देने के बजाय राज्य सरकार यूसीसी की बहस को आगे बढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आदिवासी समुदाय के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों और गारंटियों के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार से जुड़े वादों पर अब तक क्या प्रगति हुई है।

पटवारी ने आदिवासी महिलाओं के लापता होने की घटनाओं तथा आदिवासी समाज के लोगों के खिलाफ अत्याचार और शोषण के आरोपों पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि प्रभावित महिलाओं को न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा ऐसे मामलों में जवाबदेही क्यों तय नहीं हो पा रही है. यदि यूसीसी को आवश्यक माना जा रहा है तो सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इसके तहत आदिवासी परंपराओं, रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक संरक्षणों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी.

इमरजेंसी वार्ड हटाने पर गैस पीड़ितों का विरोध

निज संवाददाता

भोपाल, 22 जून. गैस पीड़ितों के चार संगठनों ने कमला नेहरू गैस राहत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड हटाकर पीईटी-सीटी केंद्र बनाने की योजना का कड़ा विरोध किया है. संगठनों ने इसे अवैध, असुरक्षित और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ बताया है.

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा की नसरीन खान ने कहा कि निविदा शर्तों के अनुसार पीईटी-सीटी केंद्र गांधी मेडिकल कॉलेज में बनाया जाना है, लेकिन इसे अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है. निविदा पाने वाली संस्था श्री अरविंदो आयुर्विज्ञान संस्थान ने भी लिखित में बताया है कि इमरजेंसी वार्ड को रेडियोलॉजी विभाग में ले जाना तकनीकी और संचालन के लिहाज से संभव नहीं है और इसमें 10 से 12 महीने लगेंगे. भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की रशीदा बी ने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं को उच्च विकिरण वाले केंद्र के साथ रखना मरीजों के लिए खतरा है और यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नियमों का उल्लंघन हो सकता है. उन्होंने बताया कि अब तक कोई स्वतंत्र विकिरण सुरक्षा जांच नहीं हुई है.

रिपोर्ट | देश में 30.6 और मध्यप्रदेश में केवल 19.6% स्कूलों में है स्मार्ट क्लास

स्मार्ट क्लासरूम के मामले में एमपी पिछड़ा

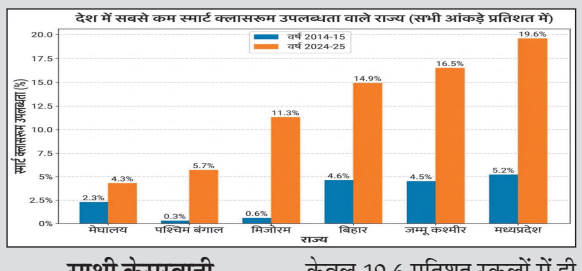

साक्षी केसरवानी

भोपाल, 22 जून. स्कूलों में पारंपरिक ब्लैक बोर्ड की जगह आधुनिकता को बढ़ावा देने स्मार्ट क्लास रूम की शुरुवात की जा चुकी है. लेकिन इस दौड़ में मध्य प्रदेश पीछे छूट गया है.

नीति आयोग द्वारा मई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, मप्र के केवल 19.6 प्रतिशत स्कूलों में ही चालू हालत में स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध है. जिसका सीधा मतलब है, कि राज्य के करीब 80 प्रतिशत स्कूलों में बच्चे आज भी आधुनिक सुविधाओं और सरकार की योजनाओं से कोसों दूर हैं. विद्यार्थियों को आधुनिकता के नाम पर स्कूलों में केवल ये शब्द ही पढ़ने को मिल रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड और पीपीटी के जरिए पढ़ाई जाने वाले एक्टिव लर्निंग की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है. हालांकि रिपोर्ट के अनुसार देशभर में साल 2014-15 में कुल 14.9 प्रतिशत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम मौजूद थे. जो कि साल 2024-25 में बढ़कर 30.6 प्रतिशत तक ही पहुंच सका है.

सबसे कम स्मार्ट क्लासरूम वाले राज्य

रिपोर्ट के मुताबिक मप्र इस मामले में देश के सबसे निचले पायदान वाले राज्यों की कतार में खड़ा है. तो वहीं डिजिटल बुनियादी ढांचे के इस ग्राफ में मेघालय में 4.3, पश्चिम बंगाल में 5.7 और मिजोरम में 11.3 प्रतिशत स्कूलों में ही ये सुविधा उपलब्ध है. इसके बाद बिहार में 14.9 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 16.5 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 19.8 प्रतिशत स्कूलों में ही स्मार्ट क्लासरूम पहुंच सके हैं. स्मार्ट क्लासरूम के मामले में देश में सबसे शानदार स्थिति चंडीगढ़ की है, जहां के 95.2 प्रतिशत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम चालू हैं. इसके बाद लक्षद्वीप में 86.1 प्रतिशत, पंजाब में 80.1 प्रतिशत, दिल्ली में 75.7 प्रतिशत और पुडुचेरी में 72.5 प्रतिशत स्कूलों में यह व्यवस्था काम कर रही है.

पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या

बैतूल. जिले के भैंसदेही क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. बहू को मायके से विदा कराने पहुंचे परिवार पर हमला हो गया. इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ग्राम जूनापानी में मरामझिरी निवासी प्रवीण मरकाम अपने परिवार के साथ बड़े बेटे की पत्नी को लेने पहुंचे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने पर लात घूंसों से हमला किया गया. हमले में प्रवीण मरकाम के बेटे आकाश मरकाम और विशाल मरकाम गंभीर रूप से घायल हो गए.

पेज एक का शेष

पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, 6 की मौत, 21 घायल

उक्त घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया जहां उपचार के दौरान एक अन्य मजदूर की मौत हो गई. 21 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. बाइक चालक के हुए दो टुकड़े इधर ट्रक और पिकअप की चपेट में एक बाइक चालक संतोष पिता केषवराव सवनेरे उम्र 46 साल ग्राम हथलेवा आ गया। बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में चालक के शरीर के दो टुकड़े हो गए. शव उठाने के दौरान कर्मी उसके शरीर को ढूढते नजर आए.

हादसे में इनकी हुई मौत

1.बब्बू पिता भूरु राजबैठे 35 साल
2.संतोष पिता केशराव सवनेरे 45 साल
3.सावित्री पति सुरेश बनके 31 साल
4.शिवकली पति तुमराम 45 साल
5.लीलावती पति गरीबा शीलू 45 साल निवासी ग्राम मचेरा
6.सुकरवती बाई पति रामचरन उम्र 40 साल निवासी ग्राम मछेरा

हादसे में ये हुए घायल

(1) करीना पिता सरवन ढीकू
(2) सुनीता पति दयाराम बनके
(3) गरिता पिता बबलू शीलू
(4) सकल बती पति गुड्डू सकोम
(5) शशीकला पति मंदर वाडिवा
6 पायल पिता महेश ठीकू
7 कंचन पिता कैलाश सकोम
8 माया पिता दशरू बट्टी
9. झुमरवती पति अम्मी लाल
10 अनीता पति संजय ढीकू
11 रोशनी पिता अजय शीलू
12 निशा पिता शंकर तुमडाम
13 सलोनी पिता सोमू वाडिवा
14 गिरजा पति किशोर वाडिवा
15 किरण पिता चंदर वाडिवा
16 हसीना पिता अजय शीलू
17 बुजवती पति रामलाल बनके
18 रविना पिता झीमा वन
19 पुजा पिता महेश ढीकू
20 आयुषी पिता सुरज बनके
21 श्याम जी पिता जंगल सिंह भोसोम

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60